उपेक्षा

सूख गए कुएं और तालाब, अब झिरिया से बुझा रहे प्यास, घुघरी के चंदना टोला में जल संकट विकराल, पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण

प्रशासन के दावों की खुली पोल, पानी को तरसे बैगा परिवार

घुघरी, नवभारत। भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही विकासखंड घुघरी के वनांचल क्षेत्रों में जल संकट ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। शासन-प्रशासन द्वारा हर घर स्वच्छ पेयजल पहुँचाने के तमाम दावों के बीच ग्राम पंचायत देवहारा के बैगा बाहुल्य क्षेत्र चंदना टोला से रूह कपा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ आदिवासी बैगा परिवार पानी की एक-एक बूंद के लिए इस तपती धूप में दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत देवहारा के चंदना टोला में स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि क्षेत्र के पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं और तालाब पूरी तरह सूखकर मैदान बन चुके हैं। ग्रामीण महिलाएं और मासूम बच्चे घंटों पानी की उम्मीद में सूखे जलस्रोतों के पास कतार लगाए बैठे रहते हैं। पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि अब ग्रामीण झिरिया के सहारे अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूषित जल के उपयोग से इन क्षेत्रों में बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है।

सरकारी विज्ञापनों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर

बताया गया कि एक ओर केंद्र और राज्य सरकार नल-जल योजना के माध्यम से हर घर पानी पहुँचाने के बड़े-बड़े विज्ञापन जारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर घुघरी के चंदना टोला जैसे आदिवासी अंचलों की हकीकत इन दावों को पूरी तरह झुठला रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को कई बार लिखित और मौखिक रूप से इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन हर बार उन्हें केवल कोरा आश्वासन ही मिला। धरातल पर पानी की एक पाइपलाइन तक नहीं पहुँची है, जिससे सरकार की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ग्रामीणों ने कहां सिर्फ चुनाव में याद आते हैं हम

स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा अब फूटने लगा है। उनका कहना है कि चुनाव के समय बड़े-बड़े नेता, जनप्रतिनिधि हाथ जोड़कर वोट मांगने आते हैं और विकास के लुभावने वादे करते हैं, लेकिन संकट के समय कोई सुध लेने वाला नहीं है। शासन की इस अनदेखी का सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब बैगा परिवारों को उठाना पड़ रहा है, जिनका जीवन पूरी तरह प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर है।

वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। चन्दना टोला के निवासियों ने जिला प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि कागजी घोड़े दौड़ाने के बजाय धरातल पर आकर उनकी प्यास बुझाने का प्रबंध करें।

गुरबिनी पुल से गिरी बाइक, एक की मौत, दूसरा गंभीर

मोटर साईकिल के उड़े परखच्चे, एम्बुलेंस की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया

घुघरी, नवभारत। घुघरी क्षेत्र के अंतर्गत गुरबिनी पुल से एक बाईक सवार तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर पुल की रैलिंग तोड़कर नीचे गिर गया। जिससे बाइक पर सवार दो युवकों में से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा बुधवार सुबह करीब 11 बजे का है। मोटर साइकिल की रफ्तार अत्यधिक तेज थी। जैसे ही वाहन गुरबिनी पुल के पास पहुँचा, बाईक चालक संतुलन खो बैठा। अनियंत्रित बाइक सीधे पुल की रेलिंग को पार करते हुए नीचे जा गिरी। बाईक की रैली से टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक काफी दूर जा गिरे।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और घुघरी पुलिस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस की मदद से दोनों को अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल युवक की स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघरी में भर्ती कराया गया है, जहाँ चिकित्सक उसकी जान बचाने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतक व घायलों की शिनाख्त की जा रही है।

बम्हनी और अंजनिया में रोजगार शिविर का आयोजन

थाना परिसर में प्रथम फाउंडेशन के सहयोग से युवाओं का चयन, युवाओं को मिला हुनर निखारने का मौका

बम्हनी/अंजनिया। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में जिले के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में थाना बम्हनी एवं चौकी अंजनिया परिसर में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण एवं चयन शिविरों का सफल आयोजन किया गया।

थाना बम्हनी परिसर में आयोजित शिविर में लगभग 40 युवक-युवतियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। शिविर के दौरान अभ्यर्थियों को जबलपुर एवं भोपाल जैसे बड़े शहरों में उपलब्ध विभिन्न ट्रेडों की जानकारी दी गई। इनमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन, हाउसकीपिंग एवं फूड एंड बेवरेज सर्विस प्रमुख रहे। चयनित अभ्यर्थियों को 12 हजार से 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन के साथ ही प्रशिक्षण के दौरान नि:शुल्क ड्रेस, जूते एवं अन्य सामग्री प्रदान की जाएगी।

अंजनिया में 32 सेक्टरों में प्रशिक्षण का विकल्प

बताया गया कि चौकी अंजनिया परिसर में आयोजित शिविर में संस्था के प्रतिनिधि प्रदीप जी ने युवाओं को 45 दिवसीय विशेष नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। यहाँ उपस्थित युवाओं को ऑटोमोबाइल, होटल मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर सहित कुल 32 विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों से अवगत कराया गया।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें बड़ी कंपनियों में रोजगार के योग्य बनाना है। पुलिस अधिकारियों ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर वे न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी योगदान दे सकेंगे। पुलिस विभाग की इस पहल की स्थानीय निवासियों और युवाओं ने काफी सराहना की है।

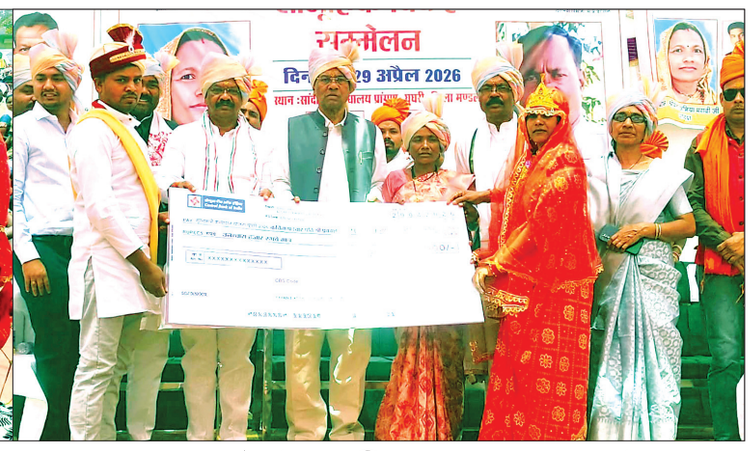

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 70 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मंडला सांसद कुलस्ते सहित कई दिग्गज रहे मौजूद

घुघरी, नवभारत। आज बुधवार को घुघरी विकासखंड के संदीपनी विद्यालय प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत एक भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी समारोह में क्षेत्र के 70 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति-रिवाज और धार्मिक परंपराओं के साथ संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते उपस्थित रहे। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा व जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम ने भी वर-वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम द्वारा इस विवाह समारोह का संचालन किया गया।

समारोह में क्षेत्र के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए, कार्यक्रम की अध्यक्ष जनिया बाई मरावी (अध्यक्ष, जनपद पंचायत घुघरी) नीरज मरकाम (भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष) रामप्रकाश साहू (जिला उपाध्यक्ष), कौशल्या मरावी एवं गीता मरावी (जिला पंचायत सदस्य), राजकुमार चौकसे (मंडल अध्यक्ष, सलवाह), संजय साहू (महामंत्री), शंभू प्रसाद साहू, सिहारे करचाम (उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत) के साथ ही समस्त जनपद सदस्य, क्षेत्र के सरपंच, सचिव और भारी संख्या में वर-वधू के परिजन उपस्थित रहे।

प्रशासनिक व्यवस्था एवं सफल आयोजन

अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) सहित जनपद पंचायत घुघरी के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों की देखरेख में कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन हुआ। शासन की इस महती योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह पूरे सम्मान के साथ कराया गया। इस अवसर पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने संबोधन में नवविवाहित जोड़ों को सुखी दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं और सरकार की इस योजना को सामाजिक समरसता और जनकल्याण का एक बेहतरीन उदाहरण बताया।

पिट लाइन और नर्मदा-विंध्य कॉरिडोर के लिए युवाओं ने खोला मोर्चा

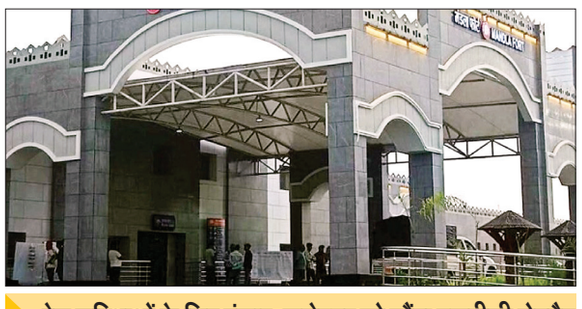

रेल सुविधाओं के लिए हुंकार, कलेक्टर को सौंपा तकनीकी रोडमैप

मंडला। जिले की वर्षों पुरानी रेल समस्याओं के समाधान और नई कनेक्टिविटी की मांग को लेकर मिशन मंडला जंक्शन - विजन 2026 अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्वतंत्र रेल कार्यकर्ता नितिन सोलंकी के मार्गदर्शन में उनके क्षेत्रीय प्रतिनिधि अखिलेश सोनी ने जिला कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मंडला को भारतीय रेलवे के मुख्य मानचित्र पर लाने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी साक्ष्यों के साथ एक ठोस रोडमैप पेश किया गया है।

पिट लाइन के अभाव में रुकी हैं लंबी दूरी की ट्रेनें

ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन और स्टेब्लिंग लाइन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इसी तकनीकी कारण से यहाँ से अयोध्या, दिल्ली, मुंबई, नागपुर और इंदौर जैसी महत्वपूर्ण दिशाओं के लिए ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। नितिन सोलंकी ने बताया कि यह मामला वर्तमान में रेल मंत्रालय के कंस्ट्रक्शन और चीफ मैकेनिकल इंजीनियर स्तर पर तकनीकी जांच के लिए प्रक्रियाधीन है। अभियान के तहत नर्मदा-विंध्य रेल कॉरिडोर पेंड्रा रोड- अमरकंटक-डिंडौरी-मंडला- गोटेगांव के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की शीघ्र स्वीकृति की मांग की गई है। इस कॉरिडोर को हाल ही में डीआरएम नागपुर ने भी सराहा है। यह रेल लाइन न केवल जनजातीय अंचलों को जोड़ेगी, बल्कि कान्हा नेशनल पार्क में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी।

पीएमओ और मन की बात तक पहुंची गूंज

विजन 2026 की गूंज अब प्रधानमंत्री कार्यालय और मन की बात कार्यक्रम तक पहुँच चुकी है। युवाओं के इस तकनीकी और योजनाबद्ध प्रयास की नगर में व्यापक चर्चा है। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से जिला स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स बनाने का आग्रह किया है, जो इन रेल परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर सके और रेलवे-प्रशासन समन्वय बैठकों में इन बिंदुओं को मजबूती से रखे।

इनका कहना है

हमारा लक्ष्य मंडला को उत्तर और दक्षिण भारत के रेल नेटवर्क से मजबूती से जोड़ना है। कवर्धा-मंडला-जबलपुर लिंक और पिट लाइन के लिए पीएमओ को ठोस प्रस्ताव भेजा गया है। जब तक पूरा अंचल रेल की मुख्यधारा से नहीं जुड़ जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
नितिन सोलंकी, स्वतंत्र रेल एक्टिविस्ट

पर्याप्त जमीन होने के बावजूद रेलवे की सुस्ती से इस अंचल का विकास रुका है और पलायन बढ़ रहा है। हमें अब आश्वासनों के लॉलीपॉप नहीं, बल्कि हकीकत में कोचिंग टर्मिनल चाहिए जिससे क्षेत्र को उसका वाजिब हक मिल सके।
अखिलेश सोनी, रेलवे जानकार

त्रिवेणी संगम घाट महाराजपुर में जमी मिट्टी हटाने की मांग

मंडला. जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल त्रिवेणी संगम घाट की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से सुधार की मांग उठाई है। समस्या निराकरण के लिए जनसुनवाई में कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपा गया। आवेदन में बताया गया कि त्रिवेणी संगम घाट जिले का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां आसपास के जिलों के साथ-साथ अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। वर्ष 2011 के सामाजिक कुंभ के पूर्व यहां घाटों का निर्माण कराया गया था, जो कुछ वर्षों तक सुरक्षित रहा, लेकिन समय के साथ यहां मिट्टी जमती गई और अब स्थिति यह है कि कई घाट पूरी तरह दब चुके हैं।

बताया गया कि वर्ष 2015 से अब तक घाटों की साफ-सफाई और रखरखाव की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिससे वर्तमान में श्रद्धालुओं को स्नान करने में कठिनाई हो रही है। साथ ही गंदगी और अव्यवस्था बढ़ने से दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। स्थानीय समिति मां नर्मदा सार्वजनिक महाआरती सेवा समिति, संतोषी माता घाट, महाराजपुर ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द घाटों पर जमी मिट्टी हटाकर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

गौतम बुद्ध की जयंती पर देवदरा में गूंजेंगे शांति के मंत्र

मंडला। विश्व को शांति और करुणा का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती पर मंडला में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दि बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इन कार्यक्रम में भक्ति, शांति और सामाजिक सरोकार का संगम देखने को मिलेगा।

बुद्धिस्ट सोसायटी के महासचिव शरद मेश्राम ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर 30 अप्रैल को शाम 6 बजे एक विशाल शांति रैली निकाली जाएगी। यह रैली नेहरू स्मारक से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक पहुँचेगी, जहाँ बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ इसका समापन होगा। इसके बाद बौद्ध विहार में चल रहे 10 दिवसीय श्रामणेर शिविर का भी विधि-विधान से समापन किया जाएगा। पूज्य भदंत धम्म दीप महानंद बोधी के सानिध्य में पूजा-वंदना, परित्राण पाठ और सभी प्राणियों के सुख-शांति हेतु मंगल मैत्री व धम्म देशना दी जाएगी। आयोजित कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे से सोसायटी द्वारा एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर की अनूठी विशेषता यह है कि रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से समिति की ओर से नि:शुल्क हेलमेट वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने प्रदेश सचिव दिलीप सोमकुंवर, जिलाध्यक्ष राज कुमार मंडाले, रेखा मेश्राम सहित राजकुमार चौधरी, सुरेश चौहान, पूनम बौद्ध और अन्य सदस्यों ने सभी अनुयायियों और नागरिकों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धम्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है।

प्रशासन मौन, पुलिस का कवच और धूल के गुबार में दफन आदिवासियों का अधिकार

खैरो टोला में रेत माफिया का तांडव, स्कूल बंद, रास्ते ध्वस्त और शिकायतों के बाद ग्रामीणों को मिल रही धमकियां

खैरो टोला/मंडला। आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरारखेड़ा का ग्राम खैरो टोला इन दिनों रेत माफियाओं का दादागिरी का अखाड़ा बन चुका है। पिछले लगभग दो माह से मां नर्मदा के सीने को चीरकर मशीनों के जरिए रेत का उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। माफिया की मशीनें न केवल नदी, बल्कि ग्रामीणों की निजी जमीनों और वन विभाग की सुरक्षित भूमि को भी अपनी जागीर समझकर रौंद रही हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि जिस मुख्य मार्ग से रेत से लदी भारी गाड़ियां गुजरती हैं, वह गांव का इकलौता मुख्य रास्ता है। रेत माफियाओं की बेतहाशा आवाजाही ने सड़क को इस कदर ध्वस्त कर दिया है कि वहां पैदल चलना भी दूभर है। आलम यह है कि सड़क पर घुटनों तक धूल जमा हो गई है। इसी मार्ग पर बच्चों का प्राथमिक स्कूल स्थित है, लेकिन भारी वाहनों के डर और धूल के कारण बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। अभिभावकों को डर है कि किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना घट सकती है। यदि कोई गंभीर बीमार हो जाए, तो गांव में एम्बुलेंस का प्रवेश करना भी अब असंभव हो चुका है।

पुलिस और प्रशासन की संदिग्ध भूमिका-हैरानी की बात यह है कि जब ग्रामीण एकजुट होकर इन गाड़ियों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो हिरदेनगर पुलिस चौकी का प्रशासन माफियाओं के बैक सपोर्ट में खड़ा नजर आता है। पुलिस माफिया पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा ग्रामीणों को ही डरा-धमका कर पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। ग्रामीणों ने इस संबंध में मंडला कलेक्टर, माइनिंग ऑफिसर हितेश बिसेन और फॉरेस्ट रेंजर लतिका तिवारी को साक्ष्यों और लोकेशन के साथ सूचना दी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन मिला। अब स्थिति यह है कि अधिकारियों ने ग्रामीणों के फोन उठाना तक बंद कर दिया है।

सीएम हेल्पलाइन की गोपनीयता पर सवाल-पीड़ित ग्रामीणों ने जब सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई, तो वहां से समाधान होने के बजाय एक नई मुसीबत शुरू हो गई। शिकायत के तुरंत बाद ग्रामीणों के पास रेत माफियाओं के फोन आने लगे और उन्हें धमकाया जाने लगा। ग्रामीणों का सवाल है कि जब शिकायत अधिकारियों और सरकारी पोर्टल पर की गई, तो उनका निजी नंबर माफियाओं तक कैसे पहुँचा? क्या प्रशासन और माफिया के बीच कोई गहरा गठजोड़ काम कर रहा है?

नियमों को ताक में रख कर रहे मशीन से उत्खनन-कानूनी रूप से रेत उत्खनन पूर्णत: अवैध नहीं हो सकता, लेकिन नियमों के मुताबिक मशीनों को लगाकर नदी का स्वरूप बिगाड़ना और निजी खेतों में जबरन मुरूम डालकर रास्ता बनाना सरासर गलत है। माफिया किसानों के खेतों को अपनी संपत्ति समझकर फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। केंद्र और राज्य में जल-जंगल-जमीन की रक्षा का दावा करने वाली भाजपा सरकार के राज में आदिवासियों के साथ हो रहा यह अन्याय कई सवाल खड़े करता है।

सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग-ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन को खुली चुनौती दी है कि यदि यह उत्खनन वैध है, तो विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नियमों की फोटो सार्वजनिक करें और बताएं कि किस नियम के तहत गांव की सड़कों और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मशीनी उत्खनन बंद नहीं हुआ और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे जिला मुख्यालय का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे।